eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक दृष्टिकोण और मिशन लाइफ (LiFE–पर्यावरण के लिए जीवन शैली)

समीर कुमार गुप्ता[1]
[1]सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), भारतीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद उ0प्र0

Received: 15 Feb 2025, Accepted & Reviewed: 25 Feb 2025, Published: 28 Feb 2025

Abstract

संपूर्ण विश्व के देशों के मध्य विकसित देश बनने की होड़ मची है और विकसित देश होने का तात्पर्य है उपभोग को जीवन शैली प्राप्त करना। विश्व के देशों के मध्य अति उपभोग के जीवन शैली अपनाने की अंधाधुंध प्रतियोगिता ने पर्यावरण क्षरण को जन्म दिया है। मानव जनित इस पर्यावरण क्षरण को रोकना वर्तमान में वैश्विक प्राथमिकता के रूप में उभरा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वैश्विक संस्थाएँ, पर्यावरण विशेषज्ञ और बहुत सारे गैर सरकारी संगठन दुनिया भर के देशों से जलवायु संरक्षण व संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के निर्वहन का आह्वान कर रहे हैं। इन परिस्थितियों मे यह आवश्यक हो गया है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण की समीक्षा की जाए और यह जानने का प्रयास किया जाए कि क्या जलवायु परिवर्तन के संबंध में विश्व द्वारा अब तक अपनाई गई रणनीति इष्टतम तथा सभी के हित में है? या फिर वर्तमान वैश्विक रणनीति में अंतर्निहित असंगति के कारण अस्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों पर केंद्रित एक पूरक लेकिन अधिक संपोषणीय रणनीति की आवश्यकता है जो कि दुनिया की सभी प्राचीन संस्कृतियों के लोकाचार मे पायी जाती है।

मुख्य शब्द – संपोषणीयता, जलवायु शमन, जीवाश्म ईंधन, जीवन चक्र लागत, हरित ऊर्जा, शून्य उत्सर्जन, फ़ीड उद्योग, मिशन 'लाइफ' (LiFE), प्रो–प्लेनेट पीपल।

Introduction

ऋग्वेद में (1/90/6,7,8) पर्यावरण को आनंदित करने और उसकी रक्षा करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए लिखा है कि–

"मधु वाताः ऋतयते मधु क्षरंति सिंधवः माद्विः नः संतुषादि।

मधु नक्तमुतुसासु मधुमात्पार्थिव राजाः मधु क्षोरस्तु सूर्यः मधिर्गबो भवंतु नः।।"

अर्थात पर्यावरण लोगों को उनके जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए आनंद प्रदान करता है। नदिया हमें पवित्र जल से आनंदित करती है और हमें स्वास्थ्य, रात्रि, सुबह, वनस्पति प्रदान करती है। सूर्य हमें शांतिपूर्ण जीवन से आनंदित करता है। हमारी गाय हमें दूध प्रदान करती है।

संपोषणीयता भारतीय लोकाचार का मूल है जो प्रकृति, अन्य लोगों, भौतिक वस्तुओं, और स्वयं के साथ हमारे संबंधों का आधार है। आज दुनिया में संपोषणीय लोकाचारों का मान्य करना और उसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो गया है। यह विडंबना ही है कि यह विचार दुनिया के उस पश्चिम से आया है जो विकास के मार्ग के रूप में अति उपभोग का समर्थन करता रहा है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत, जो कि विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, की अगले 30 वर्षों में ऊर्जा आवश्यकताएँ वैश्विक औसत से लगभग डेढ़ गुणा तेजी से बढ़ने की संभावना है। विश्व के सशक्त राष्ट्रों द्वारा भारत की जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धियों की सराहना करने की बजाय उसे विश्व के सबसे बड़े प्रदूषणकर्ताओं[1] में से एक कहा जा रहा है जबकि इस दिशा में विश्व एक बड़ा हिस्सा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में शिथिलता बरत रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (पेरिस समझौता), दिसंबर 2015 के अनुसार विश्व के 196 देशों का कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (एनडीसी) के तहत अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा जिससे कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सकें। चूँकि वैश्विक स्तर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग होगा। अतः यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या जलवायु क्षरण को रोकने के लिए अपनाई गई वैश्विक रणनीति सर्वोत्तम तथा सभी के हित में है?

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक दृष्टिकोण

प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन पहले से ही कई मौसमी और जलवायु संबंधी चरम सीमाओं को प्रभावित कर रहा है। इससे खाद्य और जल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं और समाज पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।[2] यदि हम तापमान में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप होने वाली पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए विश्व ने विभिन्न समाधानों को शामिल कर एक रणनीति अपनाई है जिसे लोकप्रिय रूप से 'जलवायु अनुकूलन' या 'जलवायु शमन' कहा जाता है। इसके अंतर्गत अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन से इतर अन्य ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना, नवीन और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील कृषि पद्धतियों को अपनाने के साथ ही साथ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना करना शामिल है।[3]

क्या वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण दोषपूर्ण है ?

प्रश्न यह है कि क्या जलवायु परिवर्तन के संबंध में वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण दोषपूर्ण है? यदि आधुनिकता और वैज्ञानिकता के पश्चिमी आइने से देखा जाए तो यहाँ दोष नजर नहीं आएगा। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? इसे समझने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण से संबंधित निम्नलिखित तर्कों को समझने की आवश्यकता है, बिना इन तर्कों समझे जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण दोषपूर्ण नही कहा जा सकता है –

1 जीवन के नियमों की दोषपूर्ण समझ

जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान वैश्विक रणनीति जीवन के नियमों के प्रति दोषपूर्ण समझ पर आधारित है। यह रणनीति अत्यंत अदूरदर्शी प्रकृति की है जो मानव निर्मित कार्यों को संपूर्ण समाधान मानने को

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

लेकर भ्रमित करती है। हमारा अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जीवन के लिए कोई भी कृत्रिम व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि मनुष्य न तो कोई नया तत्व बना सकता है, न तो प्रकृति के किसी नियम को बदल सकता है, न तो वह ऐसी किसी प्रक्रिया को संश्लेषित कर सकता जो पर्यावरण को प्रभावित करें। इसके साथ ही साथ अस्तित्व का मूल सिद्धांत हमेशा एक जैसा रहता हैं अर्थात मनुष्य को ऑक्सीजन, पानी व भोजन, उसी रूप में चाहिए होगा जिसे रूप में हम उसे जानते है। इन सबके बावजूद भी हम अपने और अन्य प्रजातियों के लिए इन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाई गई वर्तमान वैश्विक रणनीति बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त हैं।

जलवायु परिवर्तन संबंधी वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण ने विश्व के भौगोलिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी विविधता वाले विभिन्न देशों ने चिरकालिक रूप से स्वीकृत जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य नीतियों (जो कि जीवन के नियमों की सैद्धांतिक समझ पर आधारित है) पर ध्यान नहीं दिया जिस कारण से सतत विकास से संबंधित बहुत से प्राकृतिक विचारों, जैसे उपभोग पैर्टन, जीवन शैली, शाकाहार बनाम मांस आधारित अहार आदि का ध्यान नहीं रखा गया। इस प्रकार कोई भी रणनीति जिसका उद्देश्य मनुष्य की समझ या नियंत्रण से परे चीजों को बदलना है (जैसे– यह सुनिश्चित करना कि धरती का तापमान दो डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो), उसे बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर यात्रा करनी होगी।

2 अस्तित्व की परस्पर संबद्ध प्रकृति की को अनदेखी करना

जलवायु और प्रकृति आपस में एकीकृत है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे वर्तमान रणनीति नजरंदाज करते हुए ऐसे समाधानों पर बल देती है जो प्राकृतिक मूल्य श्रृंखलाओं से एकीकृत नहीं है, उदाहरणार्थ जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा का प्रतिस्थापन। यह दुर्भाग्य ही है कि नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के साथ जीवाश्म ऊर्जा के विस्थापन का समर्थन करते समय मौद्रिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अदृश्य लागतों को जीवनचक्र लागतों में शामिल नहीं किया जाता है जोकि इन विकल्पों में जलवायु लागतों की तुलना को अतुलनीय बना देता है। इस पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है कि 'एंड–टु–एंड' जीवन चक्र की लागत कितनी है? इसके अलावा एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि 100 प्रतिशत सौर और पवन प्रणालियों के लिए विशाल भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होगी जो कि असंभव रूप से बहुत ही महंगी होगी। पवन टरबाइन, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक वाहन और लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन से जुड़ें आपूर्ति से संबंधित पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।[4]

3 पृथ्वी मानव की आवश्यकताओं को तो पूर्ण कर सकती है पर मानव के लालच को नहीं

वर्तमान जलवायु परिवर्तन की रणनीति अति उपभोग वाली वैश्विक जीवन शैली में परिवर्तन के बजाय उसे जारी रखने के लिए पारंपरिक ईंधन को नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा से बदलने पर बल दे रहा है चाहे इसके लिए कम कार्बन उत्सर्जन करने वालों को अनुपातहीन रूप से उच्च भुगतान करना पड़े। यह रणनीति समस्या की जड़ (विकसित देशों में स्वीकृत अति उपभोग की जीवन शैली) पर चोट नहीं करती है बल्कि स्थिरता से एक और उद्योग बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस तरह हम संपोषणीय प्रथाओं को अपनाने के बजाय अपने बैग पर 'पेटा' (PETA) लेबल लगाने के बारे में अधिक चिंता करते

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

हैं। तथ्य यह है कि संगठन, लोग और देश उत्पादन की प्रक्रिया में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के बारे में कम चिंतित हैं, बल्कि प्रीमियम स्थानों से बाहर होने के डर से 'फेयर ट्रेड' का वैश्विक लेबल प्राप्त करने के बारे में अधिक चिंतित हैं। यह विशिष्ट क्लब अति उपभोग की ओर बढ़ने पर सवाल नहीं उठाता है बल्कि उन लेबलों पर सवाल उठाता है जिनके तहत अधिक ऊर्जा, अधिक वीडियो मनोरंजन, अधिक घर, अधिक परिवहन आदि का उपभोग होता है। यह आधुनिक जलवायु परिवर्तन रणनीति के तहत अंतर्निहित एक पाखंड है।

4 ऊर्जा खपत वाली तकनीक का वैश्विक अनुसरण

विश्व के विकसित देश एक ओर तो विकासशील देशों को जलवायु समझौतों का अनुसरण करने के लिए अत्यधिक दबाव बना रहे हैं तो दूसरी ओर वे ही अत्यधिक ऊर्जा खपत वाली 'ए.आई.' तकनीक को अपनाने में भी आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक अनुमान के अनुसार, 'गूगल' (GOOGLE) पर समान क्वेरी की तुलना में एक चैट–जीपीटी खोज दस गुणा अधिक ऊर्जा की खपत करती है। इसी प्रकार 'मेटा' के स्वामित्व वाले एक बड़े डेटा सेंटर 'आयोवा' में सिर्फ़ एक साल में ही उतनी बिजली जलने का अनुमान जिससे प्रतिदिन सात मिलियन लैपटॉप आठ घंटे काम कर सकते है।[5] फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटरों की बिजली की मांग वर्ष 2026 तक एक हजार टेरा वाट घंटा तक पहुँच सकती है। एलन मस्क ने हाल ही में 'बॉश कनेक्टेड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस' में कहा, "मैंने कभी किसी तकनीक को इससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते नहीं देखा। चिप की कमी भले ही पीछे छूट गयी हो, लेकिन ए.आई. और ई.वी. इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि दुनिया को अगले साल बिजली और ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ेगा।" 2034 तक डेटा केंद्रों द्वारा वैश्विक ऊर्जा खपत 1,580 टेरा वाट घंटा से ऊपर होने की उम्मीद है, जो कि पूरे भारत द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के बराबर है।[6] ऊर्जा की यह मांग हरित ऊर्जा उत्पादन की गति से कहीं अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। इस प्रकार पश्चिम द्वारा ए.आई. और हरित ऊर्जा को दिए जाने वाले समर्थनों की असंगति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति में अपरिहार्य असंगति पर बहुत विचार नहीं किया गया है।

5 डेटा–संचालित होने का दिखावा करता है, लेकिन प्रति व्यक्ति डेटा से कतराता है।

ऐसा कहा जाता है कि भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है इसलिए उसे बार–बार जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। परंतु इस बात को नज़र अंदाज कर दिया जाता है कि औद्योगिक क्रांति वाले पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने विकास (जीवाश्म ईंधन पर आधारित) में लापरवाही बरती, जिसके कारण दुनिया आज इस स्थिति में है। सभी आधुनिक नीति–निर्माण आधारभूत मूल्यांकन से शुरू होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश के लिए जलवायु लक्ष्य उसकी आर्थिक स्थिति के समानुपातिक हो। इसके विपरीत, यह देखा गया है कि प्रति व्यक्ति शीर्ष 10 प्रतिशत उत्सर्जकों ने 2021 में औसतन 22 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया, जो कि निचले 10 प्रतिशत द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से 200 गुना अधिक है।[7] वर्तमान सबसे बड़े उत्सर्जकों में से 85 प्रतिशत अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रहते हैं, और निचले 10 प्रतिशत उत्सर्जक अफ्रीका और दक्षिण एशिया के विकासशील देशों में रहते हैं जहाँ बिजली तक पहुँच पाना भी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

एक चुनौती है। आई.ई.ए. के अनुमान के अनुसार 2022 तक लगभग 774 मिलियन लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग उप–सहारा अफ्रीका में रहते हैं।[8] प्रति व्यक्ति खपत और उत्सर्जन में इस भारी अंतर को दर्शाते हुए, द इकोनॉमिस्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि औसत अफ्रीकी प्रति वर्ष 185 किलोवाट–घंटे की खपत करता है जबकि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः 6500 किलोवाट–घंटे और 12700 किलोवाट–घंटे की खपत करते हैं।[9] इसके विपरीत, वैश्विक आबादी का 17 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत में रहने के बावजूद इसका 1850 से 2019 के बीच वैश्विक संचयी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान केवल 4 प्रतिशत है जबकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तीन प्रतिशत ही है।[10] यह विडंबना ही है कि पश्चिम के देश विकास के मानक के रूप में प्रति व्यक्ति खपत जैसे आंकड़ों का उपयोग करते हैं लेकिन ऊर्जा उत्सर्जन का आकलन करते समय इनका पालन नहीं करते। यदि ऊर्जा उत्सर्जन का आंकलन करने में प्रति व्यक्ति खपत के मानक का प्रयोग किया जाए तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों द्वारा अधिक हरित माने जाने वाले देश भी विपरीत स्थिति में होंगे।

ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक ऊर्जा खपत में इस तरह की अत्यधिक असमानताओं के साथ, शून्य उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित या अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। देशों के लिए जलवायु समस्या की जिम्मेदारी लेना और बाहरी दबाव से मुक्त होकर सार्थक जलवायु कार्रवाई के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से काम करना महत्वपूर्ण होना चाहिए।

6 ऐतिहासिक दृष्टिहीनता और अपराध बोध का अभाव

एक ओर तो वैश्विक स्तर पर अतीत की गलतियों को सुधारने के लिये विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर अत्यधिक दबाव डालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, दूसरी ओर इस बात के पर्याप्त प्रमाण है की जलवायु परिवर्तन की समस्या की उत्पत्ति के पीछे वर्तमान विकसित देशों को प्राप्त कुछ विशेषाधिकार (उपनिवेशवाद के समय प्रगति हासिल करने के लिए वर्तमान अल्प विकसित देशों के संसाधनों का बेतहाशा दोहन) हैं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच ऊर्जा की उपलब्धता और कार्बन फुट प्रिंट में महत्वपूर्ण असमानता देखी जा सकती है। जहाँ विकसित देशों ने अपने बुनियादी ढाँचे का निर्माण निर्बाध गति से किया है, वहीं अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देश अभी भी आधारभूत बुनियादी ढाँचे की भी कमी का सामना कर रहे हैं। अल्प विकसित देशों की लगभग 55 प्रतिशत आबादी की अभी भी बिजली तक पहुँच नहीं है।[11] यूएनपी द्वारा जारी ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की तुलना में उच्च आय वाले देश छः गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और दस गुना अधिक जलवायु प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह असमानता सभी देशों (विकसित और अल्प विकसित) में शून्य उत्सर्जन के लिए एक ही समय सीमा तय करना अनुचित बनाती है।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ऊर्जा की बढ़ती मांग, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की अवहनीय लागत और जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के तिहरे खतरे का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विकसित देश पर्यावरण क्षरण में अपनी भूमिका को स्वीकार कर विकासशील देशों को संसाधन और प्रौद्योगिकी क्षमता स्थानांतरित करें जिससे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा लक्ष्य की दिशा में पूरा विश्व आगे बढ़ सके।

7 अपर्याप्त जलवायु वित्त पोषण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

शोध से पता चलता है कि विकासशील देशों को अपने मौजूदा 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (एनडीसी) लक्ष्यों का लगभग आधा हिस्सा हासिल करने के लिए 2030 तक 6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता है। इसके विपरीत, विकसित देशों ने 2020 तक केवल 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का वादा किया था, जिसमें से केवल 83.3 बिलियन अमरीकी डॉलर ही प्रदान किए गए।[12] वित्तपोषण का यह स्तर वर्तमान चुनौती के पैमाने से मेल नहीं खाता है क्योंकि विकासशील देशों की जलवायु अनुकूलन आवश्यकताओं के 2030 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2050 तक 500 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो कि वर्तमान निधि प्रवाह से 5 से 10 गुना अधिक है।

8 खाद्य आहार संतुलन

मानव का पाचन तंत्र सर्वाहारी आहार के लिए उपयुक्त है और इसी कारण मांस अपनी कैलोरी घनत्व के कारण विश्व की एक बड़ी जनसंख्या के पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 1961 से वर्ष 2000 के बीच बड़े पैमाने पर आधुनिक फ़ीड उद्योग (जो वर्तमान में विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए एक खतरा बन गया है) के विकास से उत्तरी अमेरिका मे 2.5 गुना और यूरोप में 1.7 गुना मांस उत्पादन मे वृद्धि हुई है। मांस उत्पादन की पश्चिमी पद्धति के अंतर्गत मानव खाद्य फसलों पर निर्भरता ने खाद्य–चारा प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है।[13] विश्व में कुल उत्पादित अनाज का एक तिहाई से अधिक हिस्सा पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है जबकि विश्व में 10 में से एक व्यक्ति को अभी भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता।[14] नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार प्रमुख फसलों के केवल 37 प्रतिशत क्षेत्र का ही प्रत्यक्ष खाद्य उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है जबकि मानव खाद्य फसलों का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से आधुनिक फ़ीड उद्योग से प्रतिस्पर्धी उपयोगों का सामना करता है।[15] पशुपालन के पश्चिमी तकनीक अपनाने वाले अल्प विकसित देशों में भी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और खाद्य फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को चारा फसल की खेती की ओर स्थानांतरित करने के कारण उनकी आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 600 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जबकि भूमि सीमित है। 2050 तक 10 बिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराना कोई छोटी बात नहीं है। मांस उत्पादन प्रक्रियाओं में बदलाव लाने की जरूरत है। अतः विकासशील देशों को पश्चिम की पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी असंपोषणीय प्रथाओं का अनुकरण करने से बचने के साथ ही साथ उन्हें अपना वह रास्ता भी दिखा सकते हैं जहां सदियों से खाद्य–आहार संतुलन का अभ्यास किया जाता रहा है।

अब तक के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान में प्रचलित वैश्विक रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि यह जलवायु परिवर्तन के मूल में स्थित अति उपभोग की जीवन शैली का समर्थन करती है। विकसित देशों की यह रणनीति अल्प विकसित देशों के विकास की कीमत पर अपनी जीवनशैली को बनाए रखना चाहती है। अतः जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने के लिए सार्वभौमिक रूप से कल्पित उपायों का अनुसरण करने के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल समाधानों पर विचार करना चाहिए। इसका समर्थन कई अंतरराष्ट्रीय मंचों से भी किया जाने लगा है। 2005 की जी–20 बैठक में विकास के एक ही मॉडल (ओएसएफए) को खारिज कर दिया गया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

2010–13 में संयुक्त राष्ट्र संघ न अपने 1951 के ओएसएएफ प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 2015 में एमडीजी लक्ष्यों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आर्थिक विकास को स्थानीय संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। 2015 में नीति आयोग के गठन के प्रस्ताव में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि हमें विकास के भारतीय मॉडल की जरूरत है और हमें वही करना चाहिए जो भारत में और भारत के लिए कारगर हो।

भारत की संपोषणीय जीवन शैली – मिशन लाइफ (LiFE– पर्यावरण के लिए जीवनशैली)

भारत में निवास करने वाली जनसंख्या की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों की काफी कमी है फिर भी यह देश एक महत्वाकांक्षी समाज के शिखर को छूने में सफल रहा है। देश की आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक चुनौतियों के प्रति लचीला होने की इसकी क्षमता का एक प्रमुख कारण इसकी धार्मिक प्रकृति है जो इसे एक कुशल बाजार अर्थव्यवस्था तो बनते देखना चाहती है लेकिन एक बाजारी समाज नहीं।[16] भारतीय समाज न केवल बाजारी समाज नहीं है अपितु यह मूलतः एक अनूठा समाज है जहाँ संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मानदंड और पर्यावरण, एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। "प्रकृतिः रक्षति रक्षिता"– भारत की प्राचीन जीवनशैली का मूलभूत दर्शन है जिसका अर्थ है कि ''अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी''। यह बात प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जिसमें न केवल अपार शक्ति है, बल्कि इसका अपना मन और स्वभाव भी है। चूँकि प्रकृति मनुष्य की कल्पित रणनीतियों के लिए अपने नियमों को नहीं बदलेगी, अतः हमें इसके क्रम के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार वैश्विक पर्यावरण और संपोषणीयता की रणनीति प्रकृति के चक्रीय स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए, न कि इस गलत धारणा के अनुसार कि हमारी औद्योगिक गतिविधि इसके स्वरूप को बदल सकते हैं।

पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर पिछले दशकों में कई बड़े उपाय किये गए जिनमे नीतिगत सुधार, आर्थिक प्रोत्साहन और विनियमन शामिल हैं। परन्तु अपार संभावनाओं के पश्चात भी व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों के स्तर पर आवश्यक कार्यों पर सीमित ध्यान ही दिया गया। व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार में बदलाव से ही पर्यावरण और जलवायु संकटों में कमी आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार यदि आठ अरब की वैश्विक जनसंख्या में से एक अरब लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आ सकती है।[17]

01 नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) के अवसर पर, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से शामिल करने के लिए LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के अभियान की शुरुआत की जिसमें व्यक्तियों और संस्थानों के वैश्विक समुदाय से पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए "विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय समझदारी के साथ विवेकपूर्ण उपयोग" की दिशा में LiFE को एक अंतरराष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में चलाने का आह्वान किया गया। LiFE हर किसी पर व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य डालता है कि वह ऐसा जीवन जिए जो पृथ्वी के अनुरूप हो और उसे नुकसान न पहुंचाए। ऐसी जीवनशैली का पालन करने वालों को LiFE के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

तहत "ग्रह के अनुकूल लोग" (प्रो प्लैनेट पीपल–P3) के रूप में मान्यता दी जाती है।[18] LiFE मिशन वस्तुतः प्रो प्लेनेट पीपल–P3 समुदाय के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगी जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को बनाएँ रखने में मजबूती और समर्थन प्रदान करेगी।

मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के अंतर्गत 'समझदारी के साथ विवेकपूर्ण उपयोग' की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित को बढ़ावा दिया जाता है–

- **जिम्मेदारीपूर्वक उपभोग :** जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपभोग करना और उत्पादों का उपयोग उनके जीवन चक्र के अंत तक करना।
- **प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए रहना :** वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन का पालन करते हुए सभी जीवों के साथ सामंजस्य बनाते हुए जीवन व्यतीत करना।
- **संसाधनों का संपोषणीय प्रबंधन :** अत्यधिक उपभोग वाली जीवनशैली से दूरी बनाना और संसाधनों का न्यायसंगत उपलब्धता को बढ़ावा देना।
- **सह–अस्तित्व और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना :** विज्ञान और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना, ज्ञान के आदान–प्रादान, सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रसार तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण कर देशों एवं समुदायों के बीच सह अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देना।

जीवनशैली में बदलाव लाना आसान नहीं होता। हमारी आदतें हमारे दैनिक जीवन में गहराई से समाहित होती है और हमारे पर्यावरण के कई तत्वों के माध्यम से लगातार वे मजबूत होती रहती है। परन्तु आदतों को बदलना असंभव नहीं है। एक बार में एक कदम उठाकर और प्रति दिन एक बदलाव करके हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं और पर्यावरण के अनुकूल दीर्घकालिक आदतें अपना सकते हैं। अध्ययन से पता चला है कि कम से कम 21 दिनों तक किसी क्रिया का अभ्यास करने से उसे आदत बनाने में मदद मिलती है। इस संदर्भ में 'LiFE 21– दिवसीय चैलेंज' की शुरुआत की गई है ताकि भारतीयों को 21 दिनों तक प्रतिदिन एक सरल पर्यावरण अनुकूल कार्य करने और अंततः पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके। यह एक चुनौती है कि आप अपने जीवन में प्रतिदिन एक छोटी सी चीज़ बदलें और 'प्री–प्लैनेट पीपल' बने।

मिशन LiFE अतीत से प्रेरणा लेकर, वर्तमान में कार्रवाई करके, भविष्य पर ध्यान केन्द्रित करता है। 'रिड्यूस, रीयूज़ और री–सायकिल' (Reduce, Reuse & Recycle) हमारे जीवन की मूल अवधारणाएँ हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रही है।

उपसंहार

वर्तमान में जब कई शोधों से यह तथ्य प्रमाणित हो गया है कि जलवायु क्षरण की समस्या से निपटने में वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण अपनी मूलभूत वैचारिक त्रुटि के कारण असफल रहा है, उस स्थिति में विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित पर्यावरण समर्थक लोकाचार ने एक नई रोशनी दिखाई है। इस दिशा में भारत ने कार्य करते हुए अपनी संस्कृति में रचे बसे पर्यावरण समर्थक कार्यकलापों की ओर मुड़ा, जिससे मिशन 'लाइफ' (LiFE– पर्यावरण के लिए जीवन शैली) का जन्म हुआ।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण क्षरण के बीच के संबंध को समाप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, संपोषणीय अवसंरचना अपनाना, मूलभूत सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना और सभी के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करने हेतु हरित और मर्यादित रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सामाजिक जिम्मेदारी न केवल संस्थाओं की है अपितु इसके लिए प्रत्येक उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का आनंद लेने के लिए पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं तर्कों का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्थान (UNEP) की विश्व प्रमुख इन्गेर एंडरसन ने कहा कि "हम एक तिहरे ग्रह संकट से जूझ रहे हैं—जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण व अपशिष्ट। यह संकट दशकों के अंधाधुंध एवं असतत उपभोग व उत्पादन का परिणाम है। हम किस तरह जीते और उपभोग करते हैं यह बहुत मायने रखता है"।[19]

संदर्भ सूची—

1. जलवायु आपदा को रोकने में भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, येल क्लाइमेट कनेक्शन्स, मई2024 (https://tinyurl.com/yfvvahws)
2. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन(COP 21) में 196 देशों द्वारा अपनाया गया पेरिस समझौता, दिसंबर 2015
3. आर्थिक समीक्षा 2023—24, पृष्ठ संख्या 423
4. फेकेटे, बी.एम.,बैक्सको, एम., झांग, जे.,और चेन. एम .(2023), स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स टू मिटीगेट इंटरमिटेंट रिन्युअबल एनर्जी सोर्सेस : एनालिसिस फॉर द यूएस नॉर्थ ईस्ट। फ्रंटियर्स इन एनवायरनमेंटल साइंस, 11, 1076830
5. एआई पावर ग्रिड को खत्म कर रहा है। टेक फर्म चमत्कारिक समाधान की तलाश में हैं, द वाशिंगटन पोस्ट, जून 2024।
6. एआई पहले से ही वैश्विक बिजली प्रणालियों पर कहर बरपा रहा है, ब्लूमबर्ग, जून 2024 (https://tinyurl.com/56494s6a)।
7. https://tinyurl.com/bdtf4tda
8. https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/people-without-access-to-electricity-worldwide-2012-2022
9. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/11/03/africa-will-remain-poor-unless-it-uses-more-energy?
10. EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research) Community GHG Database, a collaboration between the European Commission, Joint Research Centre (JRC), the International Energy Agency (IEA), and comprising IEA-EDGAR CO2, EDGAR CH4, EDGAR N2O, EDGAR F-GASES version 8.0, (2023)European Commission, JRC (Datasets)
11. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और UNCTAD stat के आंकड़ों पर आधारित है। (https://tinyurl.com/53cxcstz)
12. जलवायु वित्त और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य, OECD (https://www.oecd.org/en/topics/climatefinance-andthe-usd-100-billion-goal.html)
13. मक्कड़, एच.पी.एस. (2018)। खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के लिए फ़ीड मांग परिदृश्य और भोजन—नहीं फ़ीड रणनीति के निहितार्थ। एनिमल, 12(8), 1744—1754।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 02, February 2025

14. हन्ना रिची, पाब्लो रोसाडो और मैक्स रोजर (2023) – "भूख और अल्पपोषण" ऑनलाइन OurWorldInData-org पर प्रकाशित। (https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment)
15. रे, डी. के., स्लोट, एल. एल., गार्सिया, ए. एस., डेविस, के. एफ., अली, टी., और ज़ी, डब्ल्यू. (2022)। प्रत्यक्ष खाद्य उपयोग के लिए फसल की कटाई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नेचर फूड, 3(5), 367–374।
16. सरल शब्दों में कहें तो, एक बाजार अर्थव्यवस्था – जो आज विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी है – इस धारणा पर केंद्रित है कि आपूर्ति और मांग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को संचालित करती है, और कीमतें 'मुक्त बाजारों के अदृश्य हाथ' से प्राप्त होती हैं। एक बाजार समाज अक्सर बाजार अर्थशास्त्र की एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति की परिणति होता है, जिसके तहत सामाजिक रीति–रिवाज बाजार मूल्यों से भारी रूप से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उन क्षेत्रों का वस्तुकरण हो जाता है जो पारंपरिक रूप से गैर–बाजार मानदंडों द्वारा शासित थे।
17. https://www.mygov.in/life/
18. https://news.un.org/hi/story/2022/06/1058112
19. https://news.un.org/hi/story/2022/06/1058112